

राजस्थान सरकार  
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राजस्थान)

विविध :: 06/2019

प्रार्थी  
यूको बैंक, प्रधान कार्यालय  
10, वि.त्रै.म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड़)  
कोलकाता, शाखा कार्यालय  
सादड़ी जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1. मैसर्स श्री माजीसा मार्बल एण्ड ग्रेनाइट  
जरिये प्रोपराइटर श्री गुलाबनाथ देवड़ा  
पुत्र सूरतनाथ देवड़ा ग्राम जूना, पोस्ट  
सादड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली  
(राज.)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ  
फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002  
(The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement  
of Security Interest Act, 2002)

आदेश

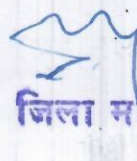
दिनांक 20/02/2019

प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,  
2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक  
अवलोकन किया गया ।

प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 बैंक के ऋणी है।  
अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी बैंक से ऋण दिनांक 13.06.2013 को 2,50,000/— (अक्षरे दो  
लाख पचास हजार रुपये) एवं दिनांक 14.06.2013 को 5,00,000/— (अक्षरे पांच लाख  
रुपये) कुल 7,50,000/— (अक्षरे सात लाख पचास हजार रुपये) अपनी वित्तीय  
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदन कर ऋण प्राप्त किया तथा ऋणी/ जमानती ने  
उपरोक्त ऋण व उस पर देय ब्याज व खर्चों के लिए अपनी प्रतिभूतिस्वरूप अचल  
सम्पति जो अप्रार्थी संख्या 01 श्री गुलाबनाथ पुत्र सुरतनाथ देवड़ा के नाम भारमुक्त  
आवासीय सम्पति जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पति पट्टा संख्या 25, बुक न.  
76 गांव जूना, ग्राम पंचायत मोरखा, तहसील देसूरी जिला पाली, राजस्थान स्थित है  
जिसका क्षेत्रफल 2593 वर्गफुट है। जिसके उत्तर में 20 फीट में रास्ते हेतु 7 फीट रोड़  
उसके बाद बनवारी नाथ का मकान, दक्षिण में हीरानाथ का प्लॉट, पूर्व में लादूनाथ का  
घर एवं पश्चिम में दरवाजा व रास्ता 7 फीट एवं गुलाबराम मेघवाल का प्लॉट है तथा  
मैसर्स श्री माजीसा मार्बल व ग्रेनाइट का दृष्टि बंधक मार्बल व ग्रेनाइट का स्टॉक  
इत्यादि। अप्रार्थी के द्वारा ऋण इकरारनामा व साम्य मूलक बंधक सृजन करने का पत्र  
आदि दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया। अप्रार्थीगण ने ऋण प्राप्त  
करने के पश्चात ऋणी/जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप ऋण खाते  
का संचालन नहीं किया जबकि अप्रार्थीगण को अपने उपरोक्त ऋण खाते का संचालन  
निष्पादित इकरारनामा के शर्तों के अनुरूप करना था। अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की  
सम्पति को प्रार्थी बैंक के पास जरिये **Mortgage by deposit of title deeds** के बंधक  
रखा। अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध शर्तों के अनुरूप उक्त खाते में लेनदेन नहीं किया  
एवं इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप देय राशि व ब्याज का भुगतान नहीं किया जो  
ऋण अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अप्रार्थीगण को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के  
अन्तर्गत नोटिस दिनांक 13.09.2018 को देकर उस दिवस तक बकाया राशि मय ब्याज  
के रूपये 2,46,490/— (अक्षरे दो लाख छियालीस हजार चार सौ नब्बे रुपये ) के मांग  
हेतु नोटिस दिया गया। देय नोशनल ब्याज व खर्चों की मांग की गई लेकिन ऋणी ने  
प्रार्थी बैंक को देय समस्त राशि का भुगतान नोटिस देने के उपरान्त भी नियत अवधि  
में नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखे  
गये स्वामित्व की सम्पत्ती का कब्जा एवं इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण  
के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के  
अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं

क्रमशः पृष्ठ :: 2

  
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

की पूर्ति हेतु रूपये 2,50,000/- (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) को 5,00,000/- (अक्षरे पांच लाख रूपये) कुल 7,50,000/- (अक्षरे सात लाख पचास हजार रूपये) का ऋण दिया उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर कर, प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये। प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किया। नोटिस प्राप्त के पश्चात भी अप्रार्थीगण ने बैंक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है :

**14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset -** (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him --

- (a) Take possession of such asset and documents relating thereto; and
- (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पाली को भेजकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति स्वरूप अपने स्वामित्व की सम्पति जो ऊपर वर्णित किया है, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना सादड़ी, जिला पाली को निर्देशित करें कि वे उक्त भूमि का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी बैंक को संभलाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की एक प्रति थानाधिकारी, सादड़ी, जिला पाली एवं प्रार्थी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सुनाया गया ।



(दिनेश चंद जैन)  
जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
11/18